भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2919
10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय-पंजाब के किसानों की आय में वृद्धि
2919. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावाः
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह तथ्य है कि किसानों की आय नहीं बढ़ रही है ;
(ख) यदि हाँ, तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(ग) क्या सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पंजाब राज्य को कोई निधि आवंटित की है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (घ): कृषि राज्य का विषय है, भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों का समर्थन करती है। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 21,933.50 करोड़ रुपये (बीई) से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 के दौरान 1,27,290.16 करोड़ रुपये (बीई) कर दिया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन जारी किया है, जिन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और संबद्ध मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के समन्वय से अपनी आय में दो गुना से अधिक वृद्धि की है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 77वें चरण (जनवरी 2019 - दिसंबर 2019) के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया था। यह सर्वेक्षण जुलाई 2018 से जून 2019 के कृषि वर्ष के संदर्भ में किया गया था। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, प्रति कृषि परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय वर्ष 2012-13 (एनएसएस 70वें चरण) में ₹6,426 से बढ़कर वर्ष 2018-19 (एनएसएस 77वें चरण) में ₹10,218 हो गई।

घरेलू उपभोग व्यय पर एनएसएसओ सर्वेक्षण (वर्ष 2023-24) के अनुसार, अखिल भारतीय औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के अनुमानों की तुलना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घरेलू व्यय में वृद्धि को दर्शाता है जो निम्नानुसार है:

क्षेत्र	विभिन्न अवधियों में औसत एमपीसीई (रु.)	
	2011-12 एनएसएस (68वां चरण)	2023-2024

ग्रामीण	1,430	4,122
शहरी	2,630	6,996

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना के तहत वर्ष 2025-26 के दौरान पंजाब को क्रमशः 481.86 करोड़ रुपये और 57.25 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त में पंजाब के 11,09,920 किसानों को 221.98 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

*****